



- कैबिनेट की सहमति के बाद चौदह खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई।
- वायु क्षेत्र और विमान ईंधन के ऊँचे मूल्य को देखते हुए एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है।
- सांसद बिष्णु पद रे ने फरारगंज तहसील के लम्बित सर्वेक्षण कार्यों को लेकर प्रशासन से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।
- श्री विजयपुरम में उपायुक्त कार्यालय में पन्द्रह मई को शत्रु सम्पत्ति ई-नीलामी के लिए बैठक होगी।



आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए किसानों को अनुमानित दो लाख साठ हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सीजन में आठ सौ चौबीस लाख मीट्रिक टन से अधिक फसल की खरीद की जाएगी। श्री वैष्णव ने कहा कि 14 खरीफ फसलों को उगाने वाले किसानों के लिए वर्ष 2014-15 से 2025-26 तक भुगतान की गई न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि अटठारह लाख निन्यानबे हजार करोड़ रुपये थी। जबकि वर्ष 2004-05 से 2013-14 तक चार लाख पच्चत्तर हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।



एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। यह फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊँचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। एयर इंडिया ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं में यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। दिल्ली-शिकागो मार्ग, मुंबई-न्यूयॉर्क मार्ग, दिल्ली-शंघाई, चेन्नई - सिंगापुर और दो अन्य मार्गों पर अस्थायी रूप से उड़ाने कम की जाएंगी।



केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड-सी.बी.एस.ई. ने आज कक्षा बारहवीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। सी.बी.एस.ई. के अनुसार सत्रह लाख अड़सठ हजार से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से पन्द्रह लाख सात हजार से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत पिचासी दशमलव दो-शून्य प्रतिशत है।



फरारगंज तहसील में चल रहे काफी समय से लंबित सर्वेक्षण एवं प्रबंधन कार्यों को लेकर सांसद विष्णु पद रे ने प्रशासन से स्वतंत्र जांच की मांग की है। उन्होंने मुख्य सचिव को इक्कीस अप्रैल को पत्र लिखकर मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है तथा इसकी प्रतिलिपि गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल को भी भेजी है। सांसद ने कहा है कि अधिसूचना जारी होने के बावजूद फरारगंज में अब तक ग्रामवार अंतिम रिकॉर्ड की स्पष्ट स्थिति सार्वजनिक नहीं की गई है। सांसद ने कहा कि सर्वेक्षण एवं प्रबंधन प्रक्रिया के चलते सामान्य राजस्व सेवाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए और जब तक नए रिकॉर्ड विधिवत अंतिम रूप से स्वीकृत नहीं होते, तब तक पुराने रिकॉर्ड के आधार पर ही नागरिक सेवाएं संचालित की जानी चाहिए।



दक्षिण अंडमान जिले के श्री विजयपुरम में 15 मई को सुबह 10 बजे उप-आयुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक और गृह मंत्रालय के तत्वावधान में प्लॉट संख्या 111/1, एबरडीन बाजार स्थित शत्रु संपत्ति की प्रस्तावित ई-नीलामी के संबंध में होगी। बैठक में अधिकारियों द्वारा नीलामी प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी तथा अधिक से अधिक

